Indian J. Soc. & Pol. 04(03):2017:135-138 **ISSN: 2348-0084(PRINT)**
Special Print Issue 2017 **UGC Journal List No 47956**

21वीं सदी में भारत–नेपाल संबंध

ममता मणि त्रिपाठी[1]

[1]एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति शास्त्र),श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,फाजिलनगर, कुशीनगर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

नेपाल भारत का पड़ोसी देश है यह एक स्थलबद्ध देश है तथा सिर्फ भारत ही उसे समुद्री मार्ग प्रदान करता है। दूसरी ओर उत्तर मे चीन के दृष्टिकोण से नेपाल की भू राजनीतिक अवस्थिति भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच आकार संसाधन, सामर्थ्य और विकास के स्तरों तथा भौगोलिक व सामाजिक–सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों जैसे कारको में विशाल अंतर के बावजूद निकट आर्थिक संबंध, भारतीय उपमहाद्वीप से तिब्बत पठार को जोड़ने वाली हिमालय की दक्षिणी ढाल पर नेपाल के संबंधों को असाधारण और घनिष्ठ बनाते है। 1950 में नई दिल्ली और काठमाण्डू ने शांति एवं मैत्री संधि और द्विपक्षीय व्यापार के एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने संबंधों को आगे बढ़ाया। 1951 में भारत लोकप्रिय रुप से दिल्ली समझौता नामक संधि पर राजा त्रिभुवन, राणाओं और नेपाली कांग्रेस की सहमति प्राप्त करने में सफल हो गया। इन संधियों ने भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट संबंधों की नींव रखी जिसने नेपाल के अधिमान्य आर्थिक व्यवहार को मान्यता दी और भारत में नेपालियों को भारतीय नागरिकों के रुप में समान आर्थिक व शैक्षणिक अवसर प्रदान किये। कमोवेश यह स्थिति 20 सदी के उत्तरार्द्ध तक बनी रही। 21 वीं सदी का आरम्भ भारत नेपाल सम्बन्धों के लिए कुछ नयी चुनौतियों के साथ हुआ । चीन का आर्थिक हथियारों का प्रयोग करते हुए लगातार दक्षिण एशिया में अपने प्रभुत्व बढ़ाने की नीति से नेपाल भी अछूता न रह सका और कभी कभी नेपाल चीन की तरफ झुकता हुआ दिखायी पड़ा है। इन विपरीत परिस्थितियों में एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते भारत ने नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों का संचालन किस प्रकार से किया है यही इस शोध पत्र का अभीष्ट है।

KEY WORDS: *भारत नेपाल संबंध, 21 वीं सदी, शांति मैत्री संधि*

1951 में नेहरु ने भारतीय संसद में यह कहा कि नेपाल पर किसी प्रकार का हमला भारत पर किया गया हमला माना जायेगा तो बी.पी0 कोइराला ने उत्तर दिया कि भारत नेपाल के अनुरोध के बिना ऐसा एकपक्षीय कदम कभी नही उठा सकता। 1974–1975 में सिक्किम के भारत में विलय की घटना की नेपाल में प्रतिक्रिया हुई किन्तु भारत ने इस बात का आश्वासन दिया कि नेपाल तथा सिक्किम में स्थितियाँ भिन्न हैं। अप्रैल 1976 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आये तो सम दूरी सिद्धान्त पर बल दिया। 1978 में भारत ने नेपाल की दीर्घकालीन माँगों को पूरा करते हुए व्यापार और परिवहन संधि को अलग करने की सहमति दे दी।1988 में जब दोनों संधियों नव संसोधन के लिए तैयार थीं तो नेपाल ने भारत की परिवहन संधि को अनुकूल बनाने की आकाँक्षाओं पर पानी फेर दिया जिसके फलस्वरुप भारत नेपाल संबंधों में गंभीर स्थिति पैदा हो गयी। नेपाल के प्रधानमंत्री कृष्णा प्रसाद भट्टाराय ने भारत नेपाल संबंधों के आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं की पुनर्स्थापना के महत्व को पहचाना और जून 1990 में भारत के प्रधानमंत्री वी0पी0 सिंह के साथ नई दिल्ली सम्मेलन में काठमाण्डू और नई दिल्ली के बीच विशेष सुरक्षा संबंधों की नए सिरे से शुरुआत की। दिसम्बर 1991 में नेपाली प्रधानमंत्री कोइराला की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नेपाल के अतिरिक्त आर्थिक लाभ के लिए नई व पृथक व्यापारिक व परिवहन संधियों पर हस्ताक्षर किये। भारत नेपाल संबंधों में तब एक नया दौर आया जब नेपाल के प्रधानमंत्री अप्रैल 1995 में नई दिल्ली आये तथा उन्होनें 1950 की शांति मैत्री संधि के व्यापक पुनरावलोकन का आग्रह किया।

1990 के दशक के अंत में भारत की उदारीकरण की नीतियों तथा गुजराल सिद्धान्त ने भारत नेपाल संबंधों पर भारी प्रभाव डाला। जून 1997 में विश्व परिवर्तनों के दौर में प्रधानमंत्री गुजराल संबंधों के एक नए युग की शुरुआत के लिए नेपाल गए। भारत सरकार ने जाने वाली नेपाल की वस्तुओं के प्रतिशत में कमी आदि। प्रधानमंत्री गुजराल की यात्रा के दौरान भारत नें बांग्लादेश के साथ वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग की नेपाल की दीर्घकालिक माँग को भी स्वीकृत दे दी। 2003 में भारत के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाली माओवादियों और भारतीय नक्सलियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल से आंध्र प्रदेश तक एक बेल्ट बनाने के प्रयास किये हैं। इसी बीच 2001 में राज्य आपात काल लागू होने से शेर बहादुर देउबा सरकार ने माओवादियों के खिलाफ प्रत्यारोपों को वापस लेने कर निर्णय किया जिसके बाद 29 जून 2003 को दोनों सरकारों और माओवादियों ने युद्धविराम की घोषणा कर दी। नेपाल 3 शक्तियों की पकड़ में फँसा हुआ है– सेना समर्थित नरेश, राजनीतिक दल और माओवादी। 1 अप्रैल 2006 में गली कूचों में 19 दिवसीय संघर्ष प्रक्रिया में नरेश ज्ञानेन्द्र को 2005 में सेना की मदद से प्राप्त की गई सत्ता को त्यागने के लिए विवश कर दिया।

1:Corresponding Author

नेपाल ने लोकतंत्र बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और तदंतर गणराज्य बनाने के लिए नेपाली संसद ने नरेश से उसकी सेना प्रमुख की उपाधि सहित उसके विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। संसद में यह भी घोषणा की कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जो देश के लक्ष्यों को निर्धारित करेगा।

काठमाण्डू संकट के समाधान हेतु नई दिल्ली को श्रेय देना उचित है माओवादियों के नेता प्रचंड ने कहा कि नेपाल में शांति की वापसी के लिए नई दिल्ली ने निर्माणात्मक भूमिका निभायी। 1980 के दशक से नेपाल में कुछ ऐसी गतिविधियाँ शुरु हुई जो भारत से नेपाल की दूरी को बढ़ाने का कार्य कर रही है इसमें विशेष मुद्दा यह था कि नेपाल द्वारा बड़े पैमाने पर चीन से हथियारों की खरीद जिसे भारत 1950 की संधि के विरुद्ध मान रहा था। परमिट व्यवस्था जिसके तहत नेपाल ने वहाँ कार्यरत 1,50,000 भारतीयों पर परमिट लागू कर दिया जबकि भारत मे 35 लाख नेपाली कार्य कर रहे थे। एक अन्य मुद्दा था नागरिकता की समस्या तथा व्यापार एवं परिगमन संधि विवाद। वर्ष 1991–94 तक भारत नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हुए लेकिन 1994 में नेपाल में साम्यवादी दल के आने से दोनों के सम्बंध में आशंकाएँ पनपने लगी हलाँकि 1996 से सम्बंध सुधरने लगे और फरवरी 1996 में नेपाल के प्रधान मंत्री देउबा की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने महाकाली नदी के विकास के बारे मे समझौता सम्पन्न करके दोनों देशों के सम्बंधों में एक नया आयाम प्रदान किया। 1997 में प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल की नेपाल यात्रा के दौरान पंचेश्वर परियोजना तैयार करने में बल दिया गया।

21वीं शदी के आरंभ के साथ ही नेपाल में तीन परिवर्तन हुए– प्रथम राजशाही का समापन, द्वितीय लोकतंत्र का आगमन, तृतीय माओवाद की विजय यद्यपि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार बनते ही नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड सितम्बर 2008 में भारत आये और अपने वक्तव्य में कहा कि वे एक संतुष्ट व्यक्ति के रुप में नेपाल जा रहे हैं उन्होंने कहा कि हम घर जाकर नेपाली नागरिको से कहेंगे कि नये युग का उदय हो रहा है उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात कर नेपाल में नये संविधान के मदद की आग्रह के साथ नेपाल के ढाँचागत विकास एवं पर्यटन के लिए भी कहा। वर्ष 2011 में भारतीय विदेश मंत्री ने नेपाल की यात्रा की और वीरगंज में भारत नेपाल सीमा पर करीब 87 करोड़ रुपये की सहायता से बनने वाली संयुक्त चेकपोस्ट की आधारशिला रखी जहाँ से दोनों देशों के बीच 75 प्रतिशत तक व्यापार होता है। 26 मई 2014 को अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क राष्ट्रों को बुलाने के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले पड़ोसी का निर्णायक कदम उठाया। 25–27 जुलाई 2014 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल की यात्रा की इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री स्तर की संयुक्त आयोग की बैठक की गयी, यह बैठक अर्थव्यवस्था, व्यापार, पारगमन, औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रित थी। 23 सालों के बाद आयोजित इस बैठक में जल संसाधनों के कई उपयोगों में सहयोग का पता लगाने के लिए बात हुई। राष्ट्रपति रामबरन यादव सहित नेपाल के नेताओं के साथ अपनी बैठकों में स्वराज ने एक समय के भीतर और समावेशी संविधान बनाने की सलाह दी जो सबके लिए स्वीकार्य हो। अपनी ओर से नेपाली प्रतिनिधि मण्डल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया साथ ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर नई सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करने की इच्छा व्यक्त की है।

नेपाल के लिए सुषमा स्वराज की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 3–4 अगस्त 2014 के काठमाण्डू के अधिकाधिक प्रवास के लिए नींव तैयार करने के लिए थी जो 12 साल के अन्तराल के बाद हो रही थी। इसके पहले अटल बिहारी बाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 2002 में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ गये थे। विकास तथा दोनों देशों के बीच एक नयी शुरुआत कायम करने के लिए निम्न समझौते पर वचार विमर्श हुआ। नेपाल के विकास की दिशा में सहायता के लिए गणमान्य अतिथि की प्रतिबद्धता, नेपाल के बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं के लिए एक विलियन डालर के रियायती ऋण की घोषणा, राजमार्गों, सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं और पारेषण नेटवर्क के निर्माण के लिए सहायता, पहले चरण में रक्सौल अमेलखगंज पेट्रोलियम– पाइपलाइन और अगले चरण में काठमाण्डू तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन की सुविधा के लिए इसका विस्तार एक साल के भीतर उर्जा से सम्बंधित चुनौतियों से निपटने और अपनी शक्ति के बुनियादी ढाँचे के उन्नत करने के लिए लम्बी देरी से चल रहे 56,000 मेगावाट पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, भारत में नेपाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाना, जैविक कृषि और हर्बल औषधि केन्द्रों को विकसित करने के लिए सहायता, सार्क सेटेलाइट के विकास, नेपाल के शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार क्षमताओं का उन्नयन करने के लिए समझौता महत्वपूर्ण है।

मोदी ने नेपाल के लिए अपनी दूसरी यात्रा 25–27 नवम्बर 2014 को की। जिससे वह सार्क की 18ठें सत्र की बैठक में भाग लेने के लिए गये थे। अगस्त 2014 में नेपाल की अपनी यात्रा के दौरान लिए गये निर्णयों में खासी प्रगति हुई है। यह यात्रा बारह समझौता पर हस्ताक्षर के मंच के रुप में सामने आई। जिसमें भारत और नेपाल के बीच समझौतों/समझौता ज्ञापनों के रुप में सबसे महत्वपूर्ण मोटर वाहन करार पर समझौता ज्ञापन था और बीच काठमाण्डू दिल्ली बस सेवा पशुपतिनाथ एक्सप्रेस को झण्डी, 900 मेगावाट की अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास

समझौते पर हस्ताक्षर, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन आदि के रुप में काठमाण्डू वाराणसी जनकपुर अयोध्या और लुम्बिनी बोध गया के बीच ट्विनिंग व्यवस्था।

सितम्बर 2015 के बाद से भारत नेपाल के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए जब वहाँ मधेशियों का आन्दोलन शुरु हुआ जिसमें उन्होंने नए संविधान में अपना अपेक्षित प्रतिनिधित्व न हो पाने का विरोध किया, उनका कहना था कि संवैधानिक ढाँचे के साथ न्याय नही किया गया। भारत में मधेशी और तराई लोगों के साथ सहानुभूति जाहिर की और फिर नेपाली नेतृत्व पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की। जिसमें उनका कहना था कि समझौते के जरिये एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए। नेपाल ने भारत पर नाकेबन्दी का आरोप लगाया जबकि भारत ने इसे एक सिरे से खारिज किया। प्रधानमंत्री ओली फरवरी 2016 में 6 दिनों के दौरे पर भारत आये और दौरे को सफल बताया।

2006 से शुरु हुए प्रयास 2015 तक जारी रही एकाएक अवरुद्ध हो गयी जल्द ही भारत नेपाल में अपनी भूमिका खो दिया। नेपाली नागरिक भी भारत के इस दौरे से नाराज थे। ओली की नाराजगी उस मसय शीर्ष पर पहुँच गई जब उन्होंने कहा कि भारत उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा है। ओली के आने से स्थितियाँ काफी बिगड़ गयी थी। नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनय मधेशी आन्दोलन के फलस्वरुप उपजी समस्या के चलते किसी दूसरे विकल्प (यानि भारत और चीन) को धमकी दे चुका था और नेपाल में इंडिया गो बैक लिखे पोस्टर काफी संख्या में दिखे जा चुके थे। लेकिन फिर भी उनकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नें यह प्रश्न रखा था कि भारत की आर्थिक प्रगति नेपाल की संपन्नता का सहज मार्ग बन सकती है। नेपाल की स्थिरता से भारत की सुरक्षा जुड़ी है नेपाल में शांति, स्थिरता, समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है और भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नही वरन् सदियों से इसका पुराना नाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि नेपाल की आर्थिक उन्नति विकास एवं सम्पन्नता में भारत की स्थायी रुचि है, भारत की आर्थिक प्रगति नेपाल की सम्पन्नता का सहज मार्ग बन सकती है। भारत नेपाल के बीच 9 समझौते हो चुके हैं जिसमें भूकम्प के पास पुनर्निमाण के लिए 25 करोड़ डालर का भारतीय अनुदान के उपयोग, नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढाँचे में सुधार, सांस्कृतिक साझेदारी, काकरभिट्ठा बांग्लादेश कारिडोर के माध्यम नेपाल और बांग्लादेश के बीच पारगमन विशाखापत्तनम बन्दरगाह का संचालन और विशाखापत्तनम से यहाँ तक के लिए रेल परिवहन का संचालन आदि शामिल है।

नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की मार्च 2016 में सम्पन्न हुई चीन यात्रा में पता चला कि नेपाल चीन की तरफ खिसक रहा है। चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10 समझौते हुए। इन समझौतों में कम से कम 5 ऐसे है जिन्हे रणनीतिक महत्व का समझा जा सकता है और उसका प्रभाव किसी न किसी रुप में भारतीय हितों पर अवश्य पड़ेगा। रणनीतिक तौर पर पहला समझौता यानि पारगमन परिवहन संबंधी समझौता महत्वपूर्ण है जिसके तहत चीन ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपने बंदरगाह के उपयोग पर सहमति दी है। नेपाल में आये भूकम्प के समय मदद करने में भारत ने तत्परता दिखायी है। हलाँकि संविधान के मुद्दे पर भारत सरकार ने असहमत मधेशियों के साथ बातचीत के माध्यम से एक आम सहमति तक पहुँचने वाली चिंताओं के विरुद्ध नरेन्द्र मोदी ने नये संविधान की घोषणा के स्वागत जिसमें उन्होंने सराहना करने के साथ ही इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर चिन्हित किया एक तरह से स्वागत योग्य है।

इस तरह दुनिया का सबसे नन्हा राष्ट्र राज्य भी इस बात को समझता है कि समकालीन दुनिया में क्षेत्रीय विस्तार असंभव है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में तो बिल्कुल ही। दक्षिण एशिया के देश पहले से ही अपने क्षेत्रीय विवाद सैन्य की जगह आर्थिक मोर्चे पर तरक्की के जरिए हल करने की कोशिश कर रहें हैं। भारत पर ओली का दोष पूरी तरह से अनावश्यक था। भारत नेपाल के नए संविधान की आलोचना जारी रखा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में और साथ ही यूरोपीय संघ समेत अन्य देशों के साथ मिलकर नेपाल की सरकार को फटकार लगाने की हद तक चला गया। यह भारत की कमजोर कूटनीति और नेपाली नेतृत्व के भीतर रसूख के कमजोर होने की ओर इशारा करती है। भारत को एक और अधिक खुला और अधिक ऊर्जावान आउटरीच का रास्ता अपनाना चाहिए जो हिमालयी गणराज्य की समग्र प्रगति के उद्देश्य से जुड़ा होता। यह निष्ठा और नेपाल की जनता के विश्वास को दूर कर भारत की मदद कर सकता था और वह भी राजनीतिक रुप से नेपाली राजनीतिक नेतृत्व के भीतर आदर सम्मान की और भारत का भुगतान किया जा सकता था।

संदर्भ

सिंह रहीस *'अंतर्राष्ट्रीय संबंध'*

Lexisnexis Haryana India, 2016

विस्वास तपन (2016) *'अंतर्राष्ट्रीय संबंध* ओरियंट ब्लॉक स्वान प्राइवेट लिमिटेड

वर्ल्ड फोकस नवम्बर 2016

Joint press statement on external affairs Minister of India visit to Nepal clause 4, 26 July 2014, *Ministery of External Affairs, Govt. of India.*

Modi Hopes to open a New chapter in Nepal *(The Statesman 3 Aug. 2014)*

Prashant Jha "How India was both Right and Wrong to Nepal" *Hindustan Times* 20 Jan 2015.

Dipanjay Roy Chaudhury "make changes constitution India to Nepal" *Economic Times* 2nd Oct 2015

Interview to Sarbendra nath Shukla of the Terai Madhes Loktantrik Party *the Telegraph* 8 Feb. 2016

R.D. Sharma "Nepal China Pen Transit Trade treaty Hina other pacts" *The Hindustan Times* 22 march 2016